जिसके संबंध में विस्तृत परिणाम प्रकाशित किये जा चुके हैं, वर्ष 1987-88 से संबंधित है (43वां दौर) अनुवर्ती सर्वेक्षण के लिए क्षेत्रीय कार्य जुलाई, 93 से जून, 94 की अवधि के दौरान पूरा किया जा चुका है। इस दौर के विस्तृत परिणाम इस वर्ष के अंत तक जारी किये जाने की आशा है। इन सर्वेक्षणों के परिणाम हमें बेरोजगारी और अल्प रोजगार की सही स्थिति आदि का मूल्यांकन करने में समर्थ बनायेंगे।

जहां तक (iii) का संबंध है, परामर्शदात्री समिति की अगली बैठक में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम के संबंध में एक नोट परिचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 1994-95 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र का इकाइयों तथा निजी क्षेत्र की इकाइयों में हुई हड़तालें

1138. **श्री नागमणि:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों तथा निजी क्षेत्र की बड़ी इकाइयों में वर्ष 1994-95 के दौरान हुई हड़तालों तथा तालाबंदियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या उदारीकरण से पूर्व के वर्षों अर्थात जुलाई, 1991 से पहले के वर्षों की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान अधिक हड़तालें तथा तालाबंदियां हुईं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी.वेंकट स्वामी): (क) वर्ष 1994 और 1995 के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की इकाइयों में हड़तालों और तालाबंदियों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ख) और (ग) उदारीकरण-पूर्व वर्षों (1989-91) की तुलना में 1994 और 1995 के दौरान कुल मिलाकर हड़तालों और तालाबंदियों की संख्या में, औद्योगिक विवादों का समय से और प्रभावी समझौते और श्रम औद्योगिक संबंधी नीतियों के विनिर्माण और कार्यान्वयन में सामाजिक सहभागियों की अंतर्ग्रस्तता के माध्यम से सरकार को सहयोग-पूर्ण भूमिका के कारण गिरावट आयी है।

विवरण

चुनिंदा राज्यों में, 1994 और 1995 के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की इकाइयों में हड़तालों और तालाबंदियों की संख्या (अनन्तिम)।

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1994			1995		
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
आन्ध्र प्रदेश	232	55	287	155	26	181
बिहार	1	24	25	0	11	11
दिल्ली	2	15	17	1	2	3
गोवा, दमन और दीव	0	6	6	0	9	9
गुजरात	20	94	114	10	78	88
हरियाणा	0	40	40	1	24	25
कर्नाटक	3	15	18	6	16	22
केरल	6	48	54	6	39	45
मध्य प्रदेश	3	17	20	13	16	29
महाराष्ट्र	14	133	147	3	79	82

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1994			1995		
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
उड़ीसा	10	28	38	6	19	25
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0
पंजाब	6	19	25	5	14	19
राजस्थान	4	40	44	3	34	37
तमिलनाडु	1	210	211	0	120	120
उत्तर प्रदेश	6	51	57	12	8	30
पश्चिम बंगाल	5	61	66	7	50	57
अन्य	3	29	32	11	21	32
कुल	316	885	1,201	239	576	815

0 = शून्य

स्रोत = श्रम ब्यूरो, शिमला।

Selection of Lady Sales Assistants in Super Bazar

1139. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the norms of selection of lady sales assistants i.e. age, qualification and status etc. in Super Bazar,

(b) the number of posts lying vacant of lady sales assistants in Super Bazar; and

(c) the authority which makes selections for these posts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPTT. OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI VENOD SHARMA): (a) It has been reported by the Super Bazar that as per their recruitment and promotion rules the sales assistants should be of the age of 18 to 28 years at the time of appointment and they should have a minimum qualification of Higher Secondary or its equivalent. No separate norms have been prescribed for lady sales assistants.

(b) Nil.

(c) The General Manager of Super Bazar is the authority for selection to these posts (sales assistants).

Survey by FICCI Regarding Exports

1140. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that FICCI in a recent survey has revealed that exports of the country are presently reeling under credit crunch;

(b) if so, the details thereof and the reaction of Government thereon; and

(c) the remedial action Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) A survey undertaken by the Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) of 100 exporters, is believed to have indicated that the inadequate availability of export credit and escalating cost of export finance is affecting the export tempo.